Statement

Shri Laxmi Narain Nayak, MP had raised under Rule 377 the following matter in the House on 6-3-1978:—

"22 Harijans Safai Karmacharis who had been working for several years in Babina Cantonment Board have been retrenched. He demanded that they should be taken back in service and all employees working in Cantonment area on a temporary basis should be made permanent".

With your permission, Sir, I want to make the whole position clear.

Every year, Station Headquarters Babina enter into an agreement with the Cantonment Board for carrying out certain works on their behalf such as removal of rubbish and filth, cleaning of roads, cleaning of roadside drains and main drains. The requirement of staff for these purposes is determined by a Board of Officers convened by the Station Headquarters for this purpose. Accordingly, during the financial year 1977-78, 207 sweepers (60 for cleaning of roads and 147 for cleaning of drains) were authorised in the conservancy agreement as per recommendations of the Board of Officers held in December 1976. For the ensuing financial year 1978-79, a fresh Board of Officers was convened by the Station Headquarters in accordance with the normal procedure to assess the requirement of conservancy staff and other services to be rendered to the troops by the Cantonment Board, Babina. The Board of Officers after carrying out physical survey of the area, recommended 183 sweepers (47 for roads and 116 for drains) amongst other conservancy staff. While recommending the revised strength of conservancy staff for the coming financial year, the Board had been guided by the need for exercising maximum economy in Defence expenditure as per instructions on the subject and observations made by the audit authorities on the conservancy agreement for the year 1977-78, with regard to provision of leave reserve etc. The Board further took into consideration the improved road conditions while deciding the revised work-load.

Based on the recommendations of the Board of Officers, 44 sweepers had to be reduced from the strength authorised for the year 1977-78. Since 18 vacancies were already available in the Cantonment Board, it was decided to retrench 26 sweepers after absorbing 18 sweepers against the existing vacancies.

The matter was, however, reviewed by Headquarters Central Command and instructions were issued by them to the President, Cantonment Board, Babina, on 27-2-1978 to the effect that no Safai Karmachari should be discharged with effect from 28-2-1978; they should continue to be in service and the conservancy agreement should be revised and for this purpose the Board of Officers should be reassembled to reassess the strength of conservancy sweepers to be employed by the Cantonment Board, Babina, in consultation with the Station Headquarters.

It has since been confirmed by the Cantonment Board authorities that all the discharged employees have been reinstated.

So far as the demand for the confirmation of temporary workers in the Cantonment area is concerned, it may be mentioned that the confirmation of temporary employees depends on the number of permanent vacancies available which are required for work of permanent nature and temporary employees are made permanent to the extent of availability of permanent vacancies in each category/grade.

12.45 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) LEGISLATION FOR EQUAL PAY FOR EQUAL WORK FOR BEEDI WORKERS IN THE COUNTRY.

श्री वीरेन्द्र प्रसाद (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में बीड़ी मजदूरों की संख्या करीब 30 लाख है जिसमें पचास हजार बिहार राज्य में है, दस हजार नालन्दा जिले में हैं। प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में अलग-अलग कानून एवं नियम हैं। इस रोजगार में भारी संख्या में लगे मजदूरों को देखते हुए उसमें एकरूपता लानी चाहिये। समान काम के लिए समान मजदूरी के आधार पर मजदूरी तय करने में सरकार को पहल करनी चाहिये। मजदूरों की व्यवस्था में सुधार हो, मालिकों के शोषण से इनको बचाने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना चाहिये। महंगाई भत्ता समय पर मिले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। नालन्दा जिले में अभी तक सरकारी आश्वासन के बावजूद भी 22 पैसे महंगाई भत्ता मजदूरों को नहीं मिल पाया। मजदूरों पर दबाव डालने के लिए मालिक काम का घंटा कम देते हैं, मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं करते।

सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। बीड़ी मजदूरों को आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिये। डाक्टर को बीड़ी गोदामों में जहां मजदूर काम करते हैं, वहां जाकर मजदूरों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिये और दवाई देनी चाहिये। इसकी भी व्यवस्था सरकार स्वयं करे या मालिकों से कराये।

(ii) IMPENDING CLOSURE OF INDUSTRIES IN SAURASHTRA REGION OF GUJARAT DUE TO SHORTAGE OF STEAM COAL ARISING FROM NON-AVAILABILITY OF WAGONS

श्री धर्मसिंहभाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, लोकसभा के नियम 377 के अन्तर्गत मैं लोक महत्व के विषय "स्टीम कोयले के वैगनों के अभाव से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के पोरबन्दर–राणावाव–मोरवी–राजकोट, भावनगर–जामनगर, जूनागढ़ वगैरह क्षेत्रों में उद्योगों का बन्द होने" के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

स्टीम कोयले के वैगनों के अभाव से हमारे गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में निम्नलिखित पांच उद्योगों या कारखानों का उत्पादन बन्द हो गया है या हो रहा है।

(1) सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज लि० राणावाव, जिला जूनागढ़ (गुजरात) की प्रतिदिन 2600 टन सीमेंट उत्पादन करने वाली इस सीमेंट फैक्टरी में से प्रति दिन 1000 टन सीमेंट उत्पादन करती हुई एक कीलन स्टीम कोयले के वैगनों के अभाव से 27-3-78 के बन्द हो गई है, इससे 700 मजदूर बेकार हो गये हैं।

इस समय फैक्टरी को प्रतिदिन 500 टन कोयले की जरूरत होती है। इसलिये फरवरी और मार्च से कोयले की तंगी या कमी प्रवर्तमान थी। अनामत कोयले का स्टाक भी खत्म हो गया। सीमेंट का पूर्ण उत्पादन करने के लिए प्रति दिन 500 टन कोयले के हिसाब से प्रति माह रेलवे के 7 वैगनों की एक रैक की जरूरत पड़ती है। राणावाव कोयले के क्षेत्र से बहुत दूरी पर है, इस सीमेंट फैक्टरी को मध्य प्रदेश की खदानों में से कोयला वैगन आते हैं। सीमेंट उत्पन्न करती, इस फैक्टरी की कीलन एक दिन बन्द रहे और दूसरे दिन चालू करें तो कम्पनी को प्रति दिन एक लाख रुपये का नुकसान होता है। क्योंकि कीलन में हुई ईटें गिर जाती हैं, इन्हें फिर लगाना पड़ता है। श्री सौराष्ट्र सीमेंट एंड कैमिकल इंडस्ट्रीज